

न्यूज ब्राफ़

अच्छे सुझावों को
विजन डॉक्युमेंट में
शामिल करेगी सरकार

अमृत विचार, लखनऊः प्रदेश सरकार

के 'समर्पण उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश' @2047 अभियान' के तहत राज्य के सभी 75 जिलों में नोडल ड्रेड शो-2025 में उन्नत कृषि संस्कृति भी आकर्षण का केंद्र बनेगी। देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों के साथ-साथ आगामी तो भी यूपी की उत्तरकांड संघटनों और आमजन से संवाद किया जा रहा है। मंगलवार तक अभियान में करीब पांच लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 4 लाख और नगरीय क्षेत्रों से करीब 4 लाख बालुगांव प्राप्त हुए हैं। सभी अधिक भागों तीरी 31 से 60 वर्ष अन्य वर्षों की दिख रही है, जबकि जन-जीवी और वर्षक नायरिकों ने भी सक्रियता दिखाई दी है। योगी सरकार अच्छे सुझावों को विजन डॉक्युमेंट में शामिल करेगी।

निर्माण श्रमिक पंजीकरण व नवीनीकरण अनिवार्य

अमृत विचार, लखनऊः श्रमिकों

के हित में उत्तर प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से कार्यवायिक संवाद सहायता योजना, मानव, शिशु व बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ग्रामीणी सहायता योजना, निर्माण कार्यालय मत्तू व दिव्यांगता सहायता योजना और अटल आवासीय विद्यालय जैसे योजनाएं सचालित हैं। बालक श्रमायुक्त सुमित कुमार ने बताया कि इन योजनाओं की बोर्ड का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक नवीनीकरण अनिवार्य है। वहले से पंजीकृत श्रमिक नवीनीकरण करते हैं। 40 प्रकार के निर्माण कार्यालय में संलग्न श्रमिक सोसायरी ई-डिस्ट्रिक्ट सेटर योगी की वेबसाइट upbocw.in से पंजीकरण या नवीनीकरण कर सकते हैं।

केजीएमयू में नहीं दिए गए दबाव के बिल

अमृत विचार, लखनऊः जीएसटी

की नई दर लागू होने के बाद

केजीएमयू के एवआरएफ काउंटरों

पर अव्यवस्था उत्तर्न हो रही है।

मंगलवार की बालुगांव प्राप्त

मरीजों-तीमादारों की खरीदी गई

दवाओं के बिल मुहुरा नहीं करये

जा सके। इससे लोगों ने नाराजी

जताई है। जीएसटी में संशोधन के

बाद दबाव सात सप्तसौदी तक सस्ती

हुई है। नई दरे सोमवार से लागू हो

गई है। मंगलवार की केजीएमयू

शाताली अस्ताल के एवआरएफ

काउंटर से किसी भी मरीज को बिल

नहीं दिए गए। इससे कुछ तीमादारों

ने नाराजी भी जताई। स्थान के

प्रवक्ता भी, कंकिष्ण से

सोपांस अपेक्षा

नहीं दिए गए। दबाव से नई दर पर ही

मुहुरा कराई जा रही है।

दबाव और समिलन लगेगा।

तीमादारों से बाद में बिल लेने को

कहा जा रहा है। दबाव से नई दर पर ही

मुहुरा कराई जा रही है।

विशेषरैया हाल में आयोजित कार्यक्रम

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में होंगे प्रदेश के एग्री 'कल्चर' के दर्शन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के साथ 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होने जा रहे हैं उत्तर इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 में उन्नत कृषि संस्कृति भी आकर्षण का केंद्र बनेगी। देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों के साथ-साथ आगामी तो भी यूपी की उत्तरकांड संघटनों और आमजन से संवाद किया जा रहा है। मंगलवार तक अभियान में करीब पांच लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। सभी अधिकारियों के प्रबोधन के बाद नोडल ड्रेड शो-2025 में उत्तर कृषि संस्कृति की विदेशी विकास का केंद्र बनेगी। देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों के साथ-साथ आगामी तो भी यूपी की उत्तरकांड संघटनों और आमजन से संवाद किया जा रहा है।

प्रदेशीर कराई। यूपी कृषि शिक्षा, बीज विकास, कृषि उपकरण, उत्तरकांड संघटन के बारे में जानकारी और एकपीछों के वैश्विक पहचान दिलाएगा। बालुगांव-2025 में यूपी की कृषि ताकत और उत्तर तकनीकों के देखकर आगंतुक 'उत्तर कृषि संस्कृति' का वास्तविक अनुभव करेंगे।

‘उन्नत कृषि संस्कृति’ का होगा अनुभव : मंत्री

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह आयोजन न केवल किसानों और एकपीछों के वैश्विक पहचान दिलाएगा बल्कि कृषि क्षेत्र में निवेश और नवाचार को भी गति देगा। विश्वास के लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 में यूपी की कृषि ताकत और उत्तर तकनीकों के देखकर आगंतुक 'उत्तर कृषि संस्कृति' का वास्तविक अनुभव करेंगे।

कृषि विभाग के नोडल अधिकारी

बीज विकास कंपनियों के लिए - डॉ. अमरनाथ मिश्र उत्तरकांड संघटन के प्रबोधन के लिए - डॉ. आशुषोष कुमार मिश्र कृषि उत्तरकांड संघटन के प्रबोधन के लिए - नरेंद्र कुमार आईआईटी कानपुर रसायन-प्रसार कंपनी के प्रबोधन के लिए - टीएम प्रियं पाटी

संस्थान, वाराणसी भी अपनी करेंगे। इनमें प्रयागराज, एटा, सहाभागिता दर्ज करेंगे।

देश-शो में 15 से अधिक लखनऊ, सिद्धार्थनगर और किसान उत्पादक संगठन गौतमबुद्धनगर समेत विभिन्न जिलों के एकपीछों के मिलेंगे।

ये संगठन अपने उत्पादों और नवाचारों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे न केवल किसानों को विपणन का अवसर मिलेगा, बल्कि उत्तर आधुनिक तकनीक और वैश्विक अनुभव से भी लाभ होगा।

कृषि विभाग की प्रदर्शनी में 17

कृषि यंत्रीकरण कंपनियों के लिए - डॉ. अमरनाथ मिश्र उत्तरकांड संघटन के प्रबोधन कंपनियों और यूपी कृषि रक्षा कंपनियों अपनी उत्पाद श्रृंखला और पेयार्थ प्रसारित करेंगे। इन तकनीकों, आधुनिक कृषि यंत्रों और जैविक खेतों से जुड़ी नयी पहले भी आगंतुकों को मिलेंगी।

कृषि विभाग की प्रदर्शनी में 29

सिंहपुर जिले के लिए विश्वराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड विकास के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा जारी, जो एक साथ हजारों लोगों को भाग तालिका में लागाए।

यहां तारा ग्रामीणी दल के लिए 64

किसान बानारा ज



भविष्य उनका है जो आज उसके लिए तैयारी करते हैं।
-मैल्कम एक्स, नागरिक अधिकारवादी

न्यायपालिका में जवाबदेही

उच्चतम न्यायालय ने जो चिंता व्यक्त की है, वह हमारे न्यायिक तंत्र की एक गहरी बिंदुनामा सामने लाती है। उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों अपने काम को समय पर पूरा करने में असमर्थ हैं और निर्णय सुनवाई के बाद लंबित रह जाते हैं। यह स्थिति न्याय की मूल भवना और जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जब एक पीड़ित अथवा वादी वर्षों तक अपने मामलों की सुनवाई का इंतजार करता है और अंततः सुनवाई पूरी होने के बाद भी फैसला टलता रहता है, तो न्याय का मूल उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने बलिल असंतोष जताया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायाधीशों के कार्य निष्पादन का योग्यता वाला अवश्यक है, ताकि जनामदारी और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित हों। न्यायपालिका लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है और इसकी विवासनीयता केवल निष्पक्षता से नहीं बल्कि समयबद्धता से भी तय होती है। यदि अदालतों में सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखकर वर्षों तक लंबित छोड़ दें, तो जनता का विश्वास टूटना स्वाभाविक है। समयावधि केवल न्यायाधीशों की व्यक्तिगत क्षमता या इच्छा शक्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि एक व्यापक व्यवस्थागत कमी है। काम का अत्यधिक बोझ, जटिल प्रक्रिया, अपर्याप्त संसाधन और तकनीकी ढांचे की कमी जैसी वातें भी इस समस्या को गहरा करती हैं।

न्यायपालिका में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का प्रश्न नया नहीं है। समय-समय पर न्यायिक सुधार की मांग होती रही है, लेकिन सुधार केवल संरचनात्मक नहीं, बल्कि मानसिकता स्तर पर भी जरूरी है। यह मान लेना कि एक बार न्यायाधीश बन जाने के बाद उसके कामकाज पर कोई प्रश्न नहीं ठड़ाया जाए, लोकतांत्रिक मूल्य के विपरीत है। किसी भी जिम्मेदारीपूर्ण पद पर कार्यरत व्यक्ति के प्रदर्शन का आकलन स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए। न्यायपालिका भी इससे अल्पीनों नहीं रह सकती। यह मूल्यांकन न केवल दोष निकालने के लिए बल्कि सुधारात्मक कदमों और क्षमता निर्माण के लिए भी होना चाहिए। न्यायिक प्रशासन में तकनीकी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। इ-कोर्ट, डिजिटल फाइलिंग और अटिंपिशियल इंटलिजेंस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम से न्यायिक कार्यवाही की अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा सकता है। निर्णय लिखने और सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को भी तकनीकी की मदद से सुव्यवस्थित किया जा सकता है, ताकि सुनवाई के बाद अन्वयक विलंब न हो।

उच्चतम न्यायालय का हालिया रुख इस बात का संकेत है कि अब समय आ गया है, जब न्यायपालिका को अतिनिरीक्षण करना चाहिए। केवल निर्णयों की गुणवत्ता नहीं, बल्कि उनकी समयबद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। न्याय में दीरी, न्याय से इंकार के समान है- यह सिद्धांत आज भी उनका ही प्रासारिक है। यदि न्यायपालिका स्वयं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है, तो लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। अतः उच्चतम न्यायालय की इस चिंता को एक चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि सुधार की दिशा में एक अवरकर की तरह देखना चाहिए। यही कदम भविष्य में न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, भरोसेमंद और नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप बना सकेगा।

प्रसंगवाद

भारतीय शोधार्थियों को प्रोत्साहन की जरूरत

पक्षियों के पंख अपने आप में संपूर्ण रूप में विकसित होते हैं, लेकिन हवा के बिना कोई भी पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। यही स्थिति भारत में नवाचारी प्रयोगाधिरूपियों के साथ रही है। उनमें कल्पनाशील असीम क्षमताएँ हैं, लेकिन कल्पनाओं को आकार देने के लिए प्रोत्साहन एवं वाचावरण नहीं मिल पाता है, हालांकि 11 साल में सतारुद्ध नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वाचावरण के निर्माण में अकल्पनीय काम किया है, किंतु अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अन्गराल फैसलों में वाचावरण कर रखे जाएंगे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर प्राप्त होने में कमी आए। ऐसी हालत में भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को कटौती कर दी जाए। दूसरी तरफ एच-1 वी वीजा के शुल्क में आवेदन के लिए एक लाख डॉलर, यानी करीब 86 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की सार्वतरंग ही रही है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वेद क्षय युवाओं के नैकरी करने के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविष्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर प्राप्त होने में कमी आए। ऐसी हालत में भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को बदला देना जरूरी है, जिसमें नवाचारी प्रतिभा है।

नासा और नेशनल फाउंडेशन के बजट में भारी कटौती के बाद यूरोप ने 'चूंच यूरोप फॉर साइंस' थीम पर मई-2025 में एक बैठक कर दिया है। फ्रांस और भारत ने बजट बढ़ा दिया है। चीन पूर्व से ही स्कूल स्तर पर छात्रों की मौलिक सोच एवं अविकार की संभावनाओं की पहचान कर रखा है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वेद क्षय युवाओं के नैकरी करने के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविष्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर प्राप्त होने में कमी आए। ऐसी हालत में भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को कटौती कर दी जाए। दूसरी तरफ एच-1 वी वीजा के शुल्क में आवेदन के लिए एक लाख डॉलर, यानी करीब 86 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की सार्वतरंग ही रही है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वेद क्षय युवाओं के नैकरी करने के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविष्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर प्राप्त होने में कमी आए। ऐसी हालत में भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को कटौती कर दी जाए। दूसरी तरफ एच-1 वी वीजा के शुल्क में आवेदन के लिए एक लाख डॉलर, यानी करीब 86 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की सार्वतरंग ही रही है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वेद क्षय युवाओं के नैकरी करने के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविष्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर प्राप्त होने में कमी आए। ऐसी हालत में भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को कटौती कर दी जाए। दूसरी तरफ एच-1 वी वीजा के शुल्क में आवेदन के लिए एक लाख डॉलर, यानी करीब 86 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की सार्वतरंग ही रही है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वेद क्षय युवाओं के नैकरी करने के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविष्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर प्राप्त होने में कमी आए। ऐसी हालत में भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को कटौती कर दी जाए। दूसरी तरफ एच-1 वी वीजा के शुल्क में आवेदन के लिए एक लाख डॉलर, यानी करीब 86 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की सार्वतरंग ही रही है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वेद क्षय युवाओं के नैकरी करने के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविष्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर प्राप्त होने में कमी आए। ऐसी हालत में भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को कटौती कर दी जाए। दूसरी तरफ एच-1 वी वीजा के शुल्क में आवेदन के लिए एक लाख डॉलर, यानी करीब 86 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की सार्वतरंग ही रही है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वेद क्षय युवाओं के नैकरी करने के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविष्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर प्राप्त होने में कमी आए। ऐसी हालत में भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को कटौती कर दी जाए। दूसरी तरफ एच-1 वी वीजा के शुल्क में आवेदन के लिए एक लाख डॉलर, यानी करीब 86 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की सार्वतरंग ही रही है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वेद क्षय युवाओं के नैकरी करने के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविष्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर प्राप्त होने में कमी आए। ऐसी हालत में भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को कटौती कर दी जाए। दूसरी तरफ एच-1 वी वीजा के शुल्क में आवेदन के लिए एक लाख डॉलर, यानी करीब 86 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की सार्वतरंग ही रही है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वेद क्षय युवाओं के नैकरी करने के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविष्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर प्राप्त होने में कमी आए। ऐसी हालत में भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को कटौती कर दी जाए। दूसरी तरफ एच-1 वी वीजा के शुल्क में आवेदन के लिए एक लाख डॉलर, यानी करीब 86 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की सार्वतरंग ही रही है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वेद क्षय युवाओं के नैकरी करने के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविष्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर प्राप्त होने में कमी आए। ऐसी हालत में भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को कटौती कर दी जाए। दूसरी तरफ एच-1 वी वीजा के शुल्क में आवेदन के लिए एक लाख डॉलर, यानी करीब 86 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की सार्वतरंग ही रही है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वेद क्षय युवाओं के नैकरी करने के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविष्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमियों को अवसर प्राप्त होने में कमी आए। ऐसी हालत में भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियो

